The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 6 | June 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF(2026): 5.6
Website: www.theacademic.in

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा में चुनौतियां

नीतू सिंह

शोध छात्रा (शिक्षाशास्त्र), जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट (उ.प्र.)

डॉ रजनीश कुमार सिंह

सहायक आचार्य (शिक्षा विभाग), जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट (उ.प्र.)

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.21470106

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: 13-05-2026

Accepted: 23-06-2026

Published: 15-07-2026

Keywords:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समावेशी शिक्षा, चुनौतियां, सुझाव|

ABSTRACT

शिक्षा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है ,जिसके माध्यम से आधुनिक समाज के प्रत्येक व्यक्ति ,वर्ग ,समूह एवं समुदायों में सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है |भारत सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग/समुदाय तक शिक्षा को समान रूप से पहुंचाने के लिए नई-नई नीतियों का निर्माण करती रहती है |राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी एक ऐसी ही शैक्षिक सुधार नीति के रूप में है, जो विद्यालय के प्रत्येक स्तर में समावेशी और समतामूलक शिक्षा का प्रावधान करती है |इस नीति का लक्ष्य" किसी भी बच्चे को पीछे न छोड़ना "एवं उद्देश्य दिव्यांग बच्चों, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों, भाषाई अल्पसंख्यकों एवं प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों सहित सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है |यह शोध-पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा के प्रावधानों एवं उनके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है |जिसके अंतर्गत चार प्रकार की चुनौतियां)भौतिक अवसंरचना एवं संसाधन, नीतिगत एवं प्रशासनिक अंतराल, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधायें तथा शिक्षक-प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (उजागर होती है| सुझाव के रूप में, इन चुनौतियों से निपटने हेतु बहु-स्तरीय रणनीति जैसे _सतत शिक्षक उन्नयन, समावेशी शिक्षा हेतु विशेष बजट, मजबूत पहुंच मानक एवं सामुदायिक भागीदारी आदि आवश्यक है |यह शोध-

Disclaimer: The opinions, interpretations, conclusions, recommendations, analyses, and statements expressed in this research article are solely those of the author(s) and do not reflect the views, policies, or positions of the Publisher, Chief Editor, Editors, Editorial Board, Reviewers, or their affiliated institutions. The author(s) are solely responsible for ensuring the originality, authenticity, and integrity of the manuscript and for ensuring that it is free from plagiarism, AI-generated content, copyright infringement, data falsification, and any other form of academic misconduct.

पत्र नीति-निर्माताओं एवं शिक्षाविदों को कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओ को समझने एवं उनके उपचार हेतु ठोस कदम उठाने में सहायक होगा|

प्रस्तावना :

व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा मानव सभ्यता का आधार स्तंभ होती है| यह केवल व्यक्ति में ज्ञानात्मक, सृजनात्मक, भावात्मक एवं सहयोगात्मक आदि गुणों का ही विकास नही करती बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों, कुरीतियों, भेदभावों एवं असमानताओं को विभिन्न नीतियों के माध्यम से दूर करने का भी प्रयास करती है| राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भी एक ऐसी अभूतपूर्व नीति है जो प्रत्येक बच्चे को चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का ही क्यों न हो_उसे शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने का संकल्प करती है|

यह नीति, समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को विद्यालय में शामिल ही नही करना चाहती बल्कि उन्हें एक ऐसा शैक्षिक वातावरण प्रदान करवाना चाहती है, जिसमें शिक्षार्थी को अपनी शैली, रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार अधिगम के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके| इसके लिए पाठ्यक्रम में लचीलापन, बहु-भाषावाद तथा डिजिटल संसाधनों की पहुंच पर जोर देने के साथ ही शिक्षक एक "मार्गदर्शक" (Facilitator) की भूमिका निभाने का कार्य करेगा|

नीति में उत्कृष्ट प्रावधान होने के बावजूद भी इन्हे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है| इनमें शिक्षक-प्रशिक्षण में कमी, ग्रामीण एवं दूरवर्ती क्षेत्र में भौतिक बुनियादी ढांचे की कम, सामाजिक पूर्वाग्रह और वित्तीय संसाधनों की कमी आदि शामिल है| राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की व्यापक दृष्टि को साकार करने के लिए इन चुनौतियों को उचित ढंग एवं बहुआयामी तरीके से समझना बहुत ही अनिवार्य है|

प्रमुख चुनौतियाँ एवं सुझाव :

समावेशी शिक्षा की सफलता में अनेक चुनौतियां सामने आती हैं जो इस प्रकार है_

I. **भौतिक अवसंरचना एवं संसाधन :** सामान्यतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने से एक शिक्षक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देना बहुत ही कठिन हो जाता है |दिव्यांग विद्यार्थियों के संदर्भ में यह बात और भी ज्यादा कठिन हो जाती है क्योंकि व्यक्तिगत ध्यान के अलावा उन्हें अनुकूलित भवन, कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, अनुकूलित शौचालय, परिवहन और विशेष उपकरण आदि की भी आवश्यकता होती है| साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को प्रदान करना और भी बड़ी चुनौती है क्योंकि

ऑनलाइन संसाधनों की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित होती है |यह विभिन्न प्रकार की चुनौतियां समावेशी शिक्षा को प्रभावित करती है|

सुझाव : इन चुनौतियों के समाधान हेतु सभी स्कूलों के लिए समान एवं अनिवार्य पहुंच मानक (जिनमें रैंप, सुलभ शौचालय, सहायक उपकरण, डिजिटल सामग्री, परिवहन आदि) निर्धारित किये जाने चाहिए| इसके अलावा ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल उपकरणों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करने के साथ स्थानीय स्तर पर निर्मित कम लागत वाले सहायक उपकरणों के विकास और वितरण को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए|

II. **नीतिगत एवं प्रशासनिक अंतराल :** नीति के प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए वित्तीय आवंटन में असमानता का होना एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके कारण दीर्घकालिक योजनायें प्रभावित होती है |इसके अलावा कार्य-योजना एवं उसकी निगरानी करने के लिए उचित तंत्र का अभाव भी एक बड़ी समस्या है|

सुझाव : इसके लिए राज्यों को एक क्रमबद्ध कार्यान्वयन योजना बनाए जाने की आवश्यकता है| साथ ही, समावेशी शिक्षा के लिए एक अलग और सुरक्षित वित्तीय कोष होना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में निरंतर और अनुमानित निवेश सुनिश्चित किया जा सके|

III. **सामाजिक-सांस्कृतिक बाधायें :** समाज में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजन) जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक पृष्ठभूमि (समावेशन में बाधा पहुंचाने का कार्य करती है जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी और अल्पसंख्यक समूहों में भेदभाव और अलगाव उत्पन्न करती है |जिसके कारण उन्हें शिक्षा से वंचित होना पड़ता है|

सुझाव : इन चुनौतियों के समाधान के लिए समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में समुदायों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाये जाना चाहिये ताकि सामाजिक भेदभाव और अलगाव की भावना को काम किया जा सके| इसके अलावा पाठ्यचर्या को विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अनुभवों और योगदानों को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाना चाहिए ताकि सभी छात्र खुद को प्रतिनिधित्व महसूस कर सके तथा स्कूल प्रशासन और शिक्षकों को भी सामाजिक विविधता, लैंगिक संवेदनशीलता और समावेशी भाषा के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है|

IV. **शिक्षक-प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण :** अधिकांश शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पहचानने, उनकी क्षमता के अनुरूप शिक्षा प्रदान कराने एवं उन्हें अनुकूलित वातावरण प्रदान कराने आदि

के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी है जिसके परिणामस्वरुप ऐसे विद्यार्थियों को सही शैक्षिक माहौल प्रदान न होने के कारण वह सामान्य विद्यार्थियों से पीछे हो जाते हैं|

सुझाव : इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षकों के लिए सतत और व्यापक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए एवं समावेशी कक्षाओं में व्यावहारिक अनुभव देने के लिए मॉडल स्कूलों और विशेष शिक्षा केंद्रों के साथ साझेदारी करने की भी आवश्यकता है तथा शिक्षकों और स्कूल प्रशासन में समावेशन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं जाना चाहिए|

निष्कर्ष :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा की दिशा में एक मजबूत नींव रखने का प्रयास किया है किंतु इसे साकार रूप देने के लिए संकल्पित, बहु-स्तरीय और संसाधन-संपन्न कार्यान्वयन रणनीति की आवश्यकता है| समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए केवल नीति का निर्माण करना ही पर्याप्त नही है बल्कि संरचनात्मक कमियों को दूर करना, शिक्षकों को सशक्त बनाना, सामाजिक बाधाओ को तोड़ना, सामुदायिक भागीदारी, संवेदीकरण कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली और वित्तीय एवं प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना भी अनिवार्य है|

अंत में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमें दृष्टि तो प्रदान कर दी है लेकिन इसका बोध समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी, राजनीतिक प्रतिबद्धता एवं संवेदनशील कार्यान्वयन पर निर्भर करता है| समावेशन केवल एक शैक्षणिक अवधारणा ही नहीं है बल्कि एक जीवन का मूल्य है जिसे साकार रूप प्रदान करना इस नीति की सच्ची कसौटी होगी|

संदर्भ :

- राव ,एस .श्रीनिवास) 2016 .(वंचितों के लिए शिक्षा :चिंताएं ,चुनौतियां और भावी योजनाएं .योजना पत्रिका , अंक)1(, पृ .सं).58-60(
- सिंह, बी. & पाण्डेय, एस. (2024). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में समावेशी शिक्षा. समावेशी शिक्षा: विविध आयाम, प्रलेक प्रकाशन) गाजियाबाद (पृ.सं.(28-40)
- Gupta, A.; Gupta, P.S.;etc) 2025(. Inclusive Challenges in Education Policy NEP 2020 Era Promises, Practices and Pitfalls. Journals of Local Self-Government, V(23). S(4). DOI: https://doi.org/10.52152/
- Rawal, M.D., & Chaurasiya, D.P. (2026). A Study on the Status and Perspectives on Inclusivity of CWSN Students. Indian Educational Review(NCERT), 63(2),p. 5-34.
- Hooque, M. A., & Chalil, K. (2026). Transforming Education in India: A Policy Framework for Rethinking Access, Equity, and Inclusive in Alignment with NEP 2020 and the Vision of Viksit Bharat@2047. Journal of Indian Education(NCERT), 50(3), p.144-172.